

किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन देने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिए

भोपाल, (प्रसं)। मध्यप्रदेश के विद्यालयों में इस वर्ष कक्षा 9 से 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं तथा कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों में प्रतिभापर्व तथा प्रोजेक्ट आधारित वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन देने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिए हैं, न ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

कोविड महामारी की परिस्थितियों में बच्चों पर मूल्यांकन संबंधी तनाव को कम करने एवं सहज वातावरण देने की दृष्टि से कोविड 19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर सत्र 2020-21 के लिए अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभापर्व) एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट/प्रोजेक्ट आधारित (होम बेस्ड एसाइनमेंट के रूप में) 18-25 फरवरी तथा 8-20 मार्च 2021 के दौरान किया गया। बच्चों ने घर पर रहकर इन वर्कशीट्स व प्रोजेक्ट को पूर्ण कर निर्धारित अवधि में कक्षा शिक्षक के पास जमा करवाया। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 30 दिसंबर 2020 को जारी निर्देशानुसार वर्कशीट मूल्यांकन उपरांत बच्चों की रिजल्टशीट तैयार कर 31 मार्च 2021 तक परीक्षा

परिणाम की घोषणा कर कक्षोन्नति दी जायेगी। कक्षा 8 सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले बच्चों को विगत सत्र अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण भी जारी किए जाएंगे। प्रदेश में 18 दिसंबर 2020 से कक्षा 9वीं से

स्कूल शिक्षा विभाग ने किया स्पष्ट

12वीं की सभी शालाएं पूर्णकालिक रूप से संचालित की जा रही है। वर्तमान में भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर की शालाओं को

छोड़कर अन्य स्थानों पर शालाएं संचालित है। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएँ 12 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है। इस के लिये विभाग द्वारा टाइम-टेबल जारी कर दिया गया है।

कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, जिसका टाइम-टेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया जा चुका है। परीक्षाओं की तैयारी के लिए शालाओं में विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जा रही है तथा उनकी सुविधा के लिये प्रश्न बैंक भी विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। ये प्रश्न बैंक, निर्धारित ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयार किए गए हैं, ताकि विद्यार्थी नियमित रूप से अभ्यास कर वार्षिक परीक्षाओं में बेहतर परिणाम अर्जित कर सकें।

छात्रों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन, होगी वार्षिक परीक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

शहर संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूली छात्रों को जनरल प्रमोशन देने के कयास पर विराम लग गया है। प्रदेश के स्कूलों में इस बार किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। कक्षा 9 से

12 की बकायदा वार्षिक परीक्षाएं होंगी और कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रतिभापर्व व प्रोजेक्ट आधारित वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंगलवार को कहा है कि इस वर्ष किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन देने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं और ना ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

यह है तैयारी

पहली से आठवीं तक में सत्र 2020-21 के लिए अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट/प्रोजेक्ट आधारित (होम बेस्ड एसाइनमेंट के रूप में) 18-25 फरवरी तथा 8-20 मार्च 2021 के दौरान किया गया। बच्चों ने घर पर रहकर इन वर्कशीट्स व प्रोजेक्ट को पूर्ण कर निर्धारित अवधि में कक्षा शिक्षक के पास जमा कराया है। वर्कशीट मूल्यांकन के बाद बच्चों की रिजल्टशीट तैयार कर 31 मार्च 2021 तक परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। प्रदेश में 18 दिसम्बर 2020 से कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल शुरू हो चुके हैं। वर्तमान में भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर शहरों में संचालित स्कूलों को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्कूल चल रहे हैं।

सीएम ने खातों में ट्रांसफर किए 1930 करोड़

77 शाला भवनों, 8 शिक्षा परिसरों व तीन छात्रावासों का किया लोकार्पण

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल

मो.नं. 9425078939

अपने चौथे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विभिन्न योजनाओं के लिए एक क्लिक के जरिए 1,930 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोटी, कपड़ा और मकान, दवाई, पढ़ाई और सबके लिए रोजगार के अवसर के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। सीएम ने इस मौके पर राज्य



मुख्यमंत्री किसान योजना में 340 करोड़ रुपए और ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ रुपए का ऋण कृषकों के खातों में सिंगल क्लिक से जारी किया। उन्होंने कहा- प्रदेश में रोजगार के हर प्रयास जारी हैं।

स्तरीय कार्यक्रम में फसल नुकसान की राहत राशि की द्वितीय किस्त के रूप में 1,530 करोड़ रुपए,

शिक्षा परिसरों तथा शाला भवनों का लोकार्पण: जनजातिय कार्य विभाग द्वारा 219.75 करोड़ की लागत से निर्मित 8 कन्या शिक्षा परिसर भवनों तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 104.74 करोड़ की लागत से निर्मित 77 शाला भवनों और तीन छात्रावासों का वर्चुअल पर लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पात्र पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी के पद पर पदोन्नति दी जा रही है। इससे करीब 1,080 टीआईडीएसपी बन सकेंगे।

छेड़छाड़ से परेशान 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या

सुसाइड नोट मिला, आरोपी युवक गिरफ्तार

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

editor@peoplessamachar.co.in

निशातपुरा में छेड़छाड़ करने वाले युवक से परेशान होकर 11वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके पास मिले सुसाइड नोट से पता चला कि मोहल्ले में रहने वाला युवक दो साल से उसे परेशान कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

एएसआई एसएल वर्मा ने बताया कि 17 वर्षीय किशोरी 11वीं में पढ़ती थी। परिवार में माता-पिता के अलावा एक बड़ा भाई है। पिता शासकीय कर्मचारी हैं। सोमवार शाम करीब सात बजे छात्रा ने घर में फांसी लगा ली। परिजनों की नजर पड़ी तो उसे फंदे से उतारकर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पास एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा था कि मोहल्ले में रहने वाला युवक दो सालों से उसे परेशान कर रहा है। कोचिंग आते-जाते समय

उसका पीछा कर अश्लील कमेंट्स करता है, जिसके कारण वह खुदकुशी कर रही है। माता-पिता के लिए उसने लिखा कि उनका कोई दोष नहीं है। युवक के बारे में पीड़िता ने परिजनों को भी बताया था। परिजनों ने युवक को समझाइश दी थी, जिसके बाद वह कुछ दिनों के लिए वह शांत हो गया था। दोबारा हरकत करने लगा तो लड़की ने खुदकुशी कर ली।

बढ़ रही छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं: नए साल के 82 दिनों में शहर में छेड़छाड़ के 99 अपराध दर्ज हो चुके हैं। इसी अवधि में बलात्कार के कुल 58 अपराध दर्ज हुए हैं।

जांच की जा रही है

मर्ग जांच के बाद आरोपी युवक के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने और पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है।

दिनेश कुमार कौशल,
एएसपी, जोन क्रमांक-4

मंत्री के सामने रो पड़ी छात्रा, कहा- जनरल प्रमोशन के बाद भी किया फेल

नूतन कॉलेज पहुंचे थे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231237

सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय (नूतन कॉलेज) में आयोजित 'मेरा मास्क मेरी सुरक्षा' कार्यक्रम में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बात करते हुए एक छात्रा रो पड़ी।

छात्रा ने मंत्री को बताया कि गत वर्ष कोरोना के कारण सभी स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया गया था। ऑनलाइन सूची में उसका नाम भी सेकंड ईयर के लिए प्रमोट किया गया। सेकंड ईयर की फीस भी

जमा कर दी है, लेकिन अब फीस लौटाते हुए दोबारा फर्स्ट ईयर में जाने को कहा जा रहा है। बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा संजू मालवीय ने कहा कि पिछले साल 31 दिसंबर तक सभी छात्राओं को असाइनमेंट जमा करना था, लेकिन गांव में होने के कारण उसे जानकारी नहीं मिल सकी। उसने जनवरी में असाइनमेंट जमा किया। लेकिन देरी से असाइनमेंट जमा करने का बोलते हुए उसे फेल कर दिया गया है। उसने प्राचार्य प्रतिभा सिंह से बात की तो उन्होंने मार्च में एक और मौका देने की बात कही थी, लेकिन अब इंकार कर दिया है।

शिक्षकों ने सीएम के नाम सौंपा मांग-पत्र

पीपुल्स संवाददाता • विदिशा

मो.नं. 9827385655

राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर राज्य शिक्षक संघ एवं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग को ज्ञापन सौंपा। जिसमें एनपीएस के स्थान पर पुरानी

पेंशन बहाल करने एवं अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग की क्रमोन्नति वेतनमान पर रोक को हटा कर यथाशीघ्र आदेश जारी किए जाए। मप्र शासन द्वारा स्वीकृत सीएम राइज स्कूल योजना जो निजीकरण को बढ़ावा देने वाला कदम है। जो कि भविष्य में घातक होगा। शासन से रोक लगाई इस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई एवं

शिक्षकों की दक्षता परीक्षा पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय महासचिव राजेश एलिया, जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, कार्यकारी जिलाध्यक्ष प्रेम नारायण परिहार, उपाध्यक्ष राम शंकर सोनी, महासचिव राजेश भूषण शर्मा, मोहन लाल मीणा, नितिन सिंह, शैलेंद्र शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

नई शिक्षा नीति में अनुसंधान परक उच्च शिक्षा पर विशेष जोर

मेपकास्ट में 36 वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस शुरू



यंग साइंटिस्ट कांग्रेस को संबोधित करते उच्च शिक्षा मंत्री और मौजूद अन्य विशेषज्ञ।

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्व-वित्त पोषण (सेल्फ फाइनेंस) कोर्स शुरू करना चाहिए, ताकि सभी युवाओं को रोजगार मिले। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को अनुसंधान परक बनाने पर विशेष जोर दिया है।

यह विचार उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मैपकास्ट के विज्ञान भवन में आयोजित 36 वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के उद्घाटन

सत्र को संबोधित कर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में सस्ती और कारगर वैक्सीन निर्माण कर दुनिया में नाम रोशन किया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि छोटी-छोटी बातों से विज्ञान जगत में बड़ी खोजें की जा सकती हैं। अध्यक्षता कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि आज आयोजित युवा वैज्ञानिक सम्मेलन प्रदेश के युवाओं में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा।

प्रोफेसर कॉलोनी स्थित विद्या विहार स्कूल का मामला

प्राचार्य के अबसेंट लगाने से नाराज शिक्षिकाएं डीईओ ऑफिस पहुंचीं

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231327

शिक्षिकाओं और प्राचार्य के बीच विवाद को लेकर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित विद्या विहार सरकारी स्कूल फिर सुर्खियों में है। मंगलवार सुबह 10 बजे स्कूल पहुंची शिक्षिकाओं को प्राचार्य ने रजिस्टर में साइन नहीं करने दिया। इसको लेकर शिक्षिकाओं ने विरोध दर्ज कराया।

शिक्षिकाओं ने कहा कि प्राचार्य ने ही 10 बजे आने को बोला। शासन का 9 बजे आने का आदेश बताकर अब अबसेंट लगा रही हैं। इस मामले को लेकर वे पहले संकुल और फिर डीईओ नितिन सक्सेना से मिलीं। डीईओ कार्यालय पहुंची शिक्षिकाओं ने बताया कि जब से शासन के आदेश हुए, तब से वे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ड्यूटी कर रही हैं। सोमवार को प्राचार्य ने कहा कि स्कूल बंद हैं और हॉस्टल में रह रही छात्राओं की पढ़ाई नहीं हुई। इसलिए मंगलवार से सभी टीचर 10 बजे आएँ और हॉस्टल में



कस्तूरबा स्कूल स्थित संकुल कार्यालय में शिकायत कर निकलती महिला शिक्षिका।

स्कूल-डीईओ ऑफिस के बीच चक्कर काट रही टीचर

इधर, प्राचार्य द्वारा एक टीचर को डीईओ कार्यालय रिलीव करने पर टीचर, डीईओ कार्यालय व स्कूल के बीच जॉइनिंग के लिए चक्कर काट रही हैं। प्रायमरी व मिडिल स्कूल अभी तक खुले नहीं हैं। प्राचार्य ने इसके चलते प्रायमरी की टीचर शुभलेश तोमर को 12वीं तक हिंदी पढ़ाने को कहा। शुभलेश ने बताया

जाकर छात्राओं को पढ़ाएं। प्राचार्य के इस मौखिक आदेश को लिखित में मांगा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मंगलवार को जब टीचर 10

कि उन्होंने हिंदी लिटरेचर से एमए किया है, इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन प्राचार्य ने रविवार को आकर पढ़ाने को कहा, तो मना कर दिया। इस पर प्राचार्य ने रिलीव कर दिया। वहीं डीईओ ऑफिस ने बिना जॉइन कराए उन्हें वापस स्कूल भेज दिया। अब, इधर प्राचार्य भी जॉइन नहीं करने दे रही हैं।

बजे पहुंचीं, तो उन्होंने लेट आना बताकर साइन नहीं करने दिया। इसको लेकर सभी टीचरों ने डीईओ को शिकायत दर्ज कराई है।

टीचर पढ़ाना नहीं चाहतीं

वहीं, इस संबंध में स्कूल की प्राचार्य निशा कामरानी का कहना है कि आयुक्त लोक शिक्षण के आदेश सुबह 9 बजे से आने के हैं, लेकिन शिक्षिकाएं सुबह 10 बजे आकर इस आदेश का उल्लंघन कर रही हैं। स्कूल बंद हैं और हॉस्टल की छात्राएं पढ़ना चाहती हैं। इसलिए हमने मानवीयता के नाते पढ़ाने को कहा है। लेकिन यह टीचर पढ़ाना नहीं चाहतीं। वार्डन के द्वारा लिखित आदेश मांगे जाने की बात सरासर झूठी है। स्कूल में छात्र संख्या के मान से अतिशय टीचर हैं, फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है।

दोनों पक्ष सुनकर निर्णय लेंगे

विद्या विहार की टीचर रजिस्टर में साइन नहीं करने की समस्या लेकर आई थीं। उनकी शिकायत सुन ली है। कल प्राचार्य का पक्ष भी सुनेंगे। दोनों का पक्ष सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

-नितिन सक्सेना, डीईओ, भोपाल

इस साल 21 हजार कर्मचारी हो जाएंगे रिटायर

सरकारी दफ्तरों की कमान 20% उम्रदराज कर्मचारियों के हाथों में

सीताराम ठाकुर • भोपाल

मो.नं. 9425078939

56 साल से अधिक आयु के करीब एक लाख कर्मचारियों के हाथों में सरकारी दफ्तरों की कमान है। यानी बुजुर्ग होने की कगार पर पहुंचे इन कर्मचारियों में बड़ी-बड़ी फाइलें उठाने की ताकत नहीं बची है। इनमें करीब 22 हजार 544 कर्मचारी तो 60 साल की आयु को पार कर चुके हैं।

इस साल 21 हजार कर्मचारी रिटायर होने जा रहे हैं। उधर, अधिकारियों की बात की जाए तो 18 से 35 साल के युवा अफसरों की संख्या महज 420 है।

सालों से रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने की वजह से प्रदेश में सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। वैसे बीते साल जिलों में करीब 10 हजार कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। इस साल 21 हजार कर्मचारी सरकारी सेवा को अलविदा करने जा रहे हैं। वर्तमान में सरकारी दफ्तरों में नियमित कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या 5 लाख 54 हजार 991 है। इनमें प्रथम श्रेणी के



पीपुल्स समाचार पड़ताल

किस आयु वर्ग के कितने कर्मचारी

| आयु वर्ग | संख्या | आयु वर्ग | संख्या |
|----------|--------|----------------|----------|
| 18 से 21 | 3504 | 41 से 45 | 80958 |
| 22 से 25 | 20054 | 46 से 50 | 82041 |
| 26 से 30 | 47404 | 51 से 55 | 87056 |
| 31 से 35 | 64171 | 56 से 60 | 75592 |
| 36 से 40 | 71667 | 60 से अधिक आयु | 22544 |
| | | कुल नियमित | 5,54,991 |

अधिकारी 8162, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी 32 हजार 426, तृतीय श्रेणी वर्ग के कर्मचारी 4 लाख 49 हजार 806 तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 64 हजार 507 है। सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा 51 से 55 साल आयु वर्ग के 87 हजार 56 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं।

बैकलॉग के पद भी पड़े खाली

बैकलॉग के करीब 19 हजार पद सालों से खाली पड़े हुए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए सरकार वर्ष 2002-03 से लगातार विशेष भर्ती अभियान चला रही है। उधर, शिक्षकों के 40 हजार, पुलिस कर्मचारियों के 18 हजार, पटवारी, राजस्व निरीक्षक सहित अन्य विभागों में 80 हजार पद खाली हैं।

34 साल से नहीं हुई भर्तियां

जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर वर्ष 1986 से भर्तियां नहीं हुई हैं। मंत्रालय में दस साल बाद पिछले साल दबाव के चलते भर्तियां की गई थी। ट्रेड यूनियन समाप्त होते जा रही हैं और सरकार आउट सोर्स के सहारे काम चला रही है। आने वाले समय में कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो जाएगी।



सुधीर नायक, अध्यक्ष, मंत्रालय कर्मचारी संघ

सरकारी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया जारी

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर पीएससी तथा तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती करने के लिए पीईबी को जिम्मेदारी दी गई है।



रिक्त पदों पर भर्ती का काम जल्द होगा। साथ ही बैकलॉग के खाली पदों को भरने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार देने की नीति बनाई जा रही है।

विनोद कुमार, एसीएस, जीएडी

बीयू में परीक्षाएं पांच अप्रैल से, कोरोना से बचने के लिए किए जाएंगे इंतजाम

भोपाल। कोरोना संक्रमण के बीच बीयू में 5 अप्रैल से परीक्षाएं होंगी। इससे शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतने होंगे। विवि प्रशासन ने परीक्षाओं को संचालित करने के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। दूसरे और तीसरे वर्ष की यह परीक्षाएं तीन पाली में होंगी। हर पाली के बाद परीक्षा कक्ष को सेनिटाइज किया जाएगा। छात्र परीक्षा शुरू होने से पहले और बाद में आपस में चर्चा नहीं करेंगे।

एजाम

यूजी कोर्स के परीक्षा आवेदन 31 मार्च तक भर सकेंगे स्टूडेंट्स

भोपाल। बीयू ने स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए मैनेजमेंट, बीबीए, बीसीए और बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रम शामिल हैं। विलंब शुल्क 300 रुपए के साथ आवेदन 1 से 4 अप्रैल तथा विशेष विलंब शुल्क 1000 रुपए के साथ आवेदन 6 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने के सात दिन पहले तक किए जा सकेंगे।

बीयू

स्कूलों में चना-मुरमुरे खिलाने का आदेश विभाग ने किया निरस्त

भोपाल। हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों में पढ़ रहे निर्धन तबके के विद्यार्थियों को चना मुरमुरे खिलाने के आदेश को स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। ज्ञात हो कि आयुक्त लोक शिक्षण ने दो दिन पहले ही इस बारे में आदेश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि स्कूल लगने का समय सुबह 9 से 5 बजे तक का है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के माता-पिता टिफिन व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं।

व्यवस्था

एनएसयूआई ने की ओपन बुक पद्धति से परीक्षाएं कराने की मांग

पीपुल्स संवाददाता • गुना

मो.नं. 9425119633

कोरोना के बढ़ते प्रकोप से विद्यार्थियों में भी अब खौफ नजर आने लगा है। यही वजह है कि अब विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा की जगह ओपन बुक सिस्टम से करवाने की मांग उठा रहे हैं। इसके लिए एनएसयूआई ने मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

जिसमें परीक्षा ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से करवाने की मांग उठाई है। उल्लेखनीय है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म भरने का

नोटिफिकेशन जारी हुआ है। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। हालांकि फिलहाल तो परीक्षा फॉर्म पोर्टल पर ही नहीं खुल रहे हैं। विवि के अनुसार परीक्षा अप्रैल प्रथम सप्ताह में होंगे। इस आदेश के बाद विद्यार्थी परीक्षा को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर परीक्षा कैसे होगी? क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने भले ही परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली हो, लेकिन विद्यार्थियों में कोरोना को लेकर डर भी बढ़ रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा।

नेहरू कॉलेज का विधायक यादव ने किया निरीक्षण

अनियमितताएं मिलने पर जाहिर की नाराजगी

पीपुल्स संवाददाता • सागर/देवरी

मो.नं. 9826021098

शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालेज में लंबे समय से चल रही अनियमितताओं एवं गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने कॉलेज का निरीक्षण किया। जिसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी एवं अनियमितताएं देखने को मिली। जिसको लेकर विधायक हर्ष यादव ने आक्रोश जाहिर करते हुए कॉलेज प्रबंधन को फटकार लगाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये। निरीक्षण के दौरान कॉलेज परिसर में सबसे बड़ी लापरवाही उस वक्त देखने को मिली जब विधायक कॉलेज के गार्डन में पहुंचे। जहां



प्राचार्य द्वारा बड़े पैमाने पर वर्षों पुराने हरे-भरे वृक्षों पर आरा मशीन चलवाकर उन्हें कटवाकर गार्डन को वीरान बनाया। जिस बात को लेकर विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्राचार्य से पूछा कि पेड़ काटने की अनुमति किसने दी? तो जवाब में प्राचार्य ने जवाब में टाला-मटोली करते हुए कहा कि राजस्व विभाग से परमिशन लेने के बाद पेड़ों को काटा गया है।

सात हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। सरकारी हाईस्कूल-हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से परेशान स्कूल शिक्षा विभाग करीब सात हजार अतिथिशिक्षकों को नियुक्त करेगा।

लोकशिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री क्वियावत ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्यों को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूल नहीं खुले। अब अगला शैक्षणिक सत्र भी शुरू होना है। जिसे देखते हुए शिक्षकों के खाली पद भरे जा रहे हैं। हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी में शिक्षकों के करीब सात हजार पद खाली हैं। जिन्हें भरने के लिए कहा गया है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने की सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा, अब पास के कॉलेज में मिलेगा एडमिशन

नामांकन है तो दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं

हरिगूमि न्यून ►► गोपाल

सत्र 2021-22 में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रवेश के समय विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी दस्तावेजों को ऑनलाइन स्कैन कर लिया जाएगा, जिससे उन्हें महाविद्यालयों में सत्यापन के लिए बार-बार दस्तावेज नहीं ले जाना पड़ेगा। वहीं ऑनलाइन जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्रों को स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी। यदि विद्यार्थी ने एक बार नामांकन करा लिया है तो दोबारा दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यार्थियों को पास के कॉलेजों और उनकी वरीयता अनुसार प्रवेश दिया जाए।

यह निर्देश उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत सत्र 2021-22 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सत्र 2021-22 के अंतर्गत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को सुविधाजनक एवं पारदर्शी ढंग से प्रवेश लेने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

खास बातें

- बैठक में सरकारी नीतियों में संशोधन विद्वानों से लिए गए सुझाव
- प्रवेश प्रक्रिया को किया जाएगा अधिक सरल



समय-सीमा खत्म होने के बाद रिक्त सीटों को भरने प्राचार्य अधिकृत

मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रवेश की समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद रिक्त सीटों को भरने के लिए प्राचार्यों को अधिकृत किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों में संशोधन पर भी चर्चा की। उपस्थित विद्वानों से इस संबंध में सुझाव लिए गए। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन सहित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी एवं निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य और संचालक उपस्थित थे।

नूतन कॉलेज में मंत्री के सामने रो पड़ी छात्रा, बोली-नहीं मिला जनरल प्रमोशन

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने नूतन कॉलेज में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर सुबह 11 बजे सायरन बजाकर छात्राओं को मास्क लगाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने छात्राओं से कहा कि कोरोना से बचाव के लिये मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। इस दौरान मंत्री ने कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। इस बीच मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कार्यक्रम में उस वक्त सज्जाटा छा गया, जब एक छात्रा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बात करते हुए रो पड़ी। बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा संजू मालवीय ने मंत्री को बताया कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण सभी स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया गया था। ऑनलाइन सूची में उसका नाम भी सेकंड ईयर के लिए प्रमोट किया गया, मैंने सेकंड ईयर की फीस भी जमा कर दी है, लेकिन अब फीस लौटाते हुए दोबारा फर्स्ट ईयर करने को कहा जा रहा है।

मंत्री यादव ने छात्राओं को दिलाया मास्क पहनने का संकल्प



असाइनमेंट जमा नहीं होने से छात्रा को कर दिया फेल

छात्रा ने बताया कि कोरोना के कारण वह अपने गांव में थी। 31 दिसंबर तक सभी छात्राओं को असाइनमेंट जमा करना था, लेकिन गांव में होने के कारण उसे जानकारी नहीं मिल सकी। जब वह जनवरी में असाइनमेंट जमा करने पहुंची तो असाइनमेंट तो जमा कर लिया गया, लेकिन बाद में देरी से असाइनमेंट जमा करने का बोलते हुए उसे फेल कर दिया गया है। छात्रा ने मंत्री से मदद मांगी, जिसके बाद मंत्री ने कॉलेज प्रबंधन से चर्चा करने का सुझाव दिया।

आरजीपीवी : नैनोटेक्नोलॉजी विभाग में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के स्कूल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी

आयोजन

विभाग में तीन दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। विभाग की डायरेक्टर प्रो. पूर्णिमा स्वरूप खरे ने तीनों दिन होने वाले सेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉ. गगन कांत त्रिपाठी, प्रोफेसर प्रदीप खरिया, प्रोफेसर प्रियवन्द बुंदेला सहायक प्राध्यापक स्कूल ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी विभाग है।

कर्मचारी पैनल ने रखा अपना-अपना पक्ष

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मंत्रालय कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी के चुनाव भले ही स्थगित हो गए हैं लेकिन चुनाव लड़ने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल व नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैनल के पदाधिकारी आम कर्मचारियों को साधने की कवायद में लगे हैं।

मंगलवार को दोनों पैनलों की तरफ से अपनी-अपनी बातें रखी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पैनल के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के बीच पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैनल द्वारा लगाई आपत्ति व सोमवार किए गए हंगामे पर अपना पक्ष रखा है।

वल्लभ भाई पटेल पैनल के तर्क

- पैनल के सुधीर नायक व राजकुमार पटेल ने कहा कि सोमवार का हंगामा सुनियोजित था। चंद्र कर्मचारियों ने अभद्रता की, मारपीट भी कर सकते हैं। आगे माहिल खसब हो सकता है।
- मतदाता सूची नियमों के अनुरूप तैयार की गई, उसमें कोई कमी नहीं है।
- सुभाष चंद्र बोस पैनल के लोग दिसंबर से चुनाव का प्रचार करने लगे थे और बैठकों में कहते थे कि चुनाव कराओ। जबकि उस समय मंत्रालयीन कर्मचारी संघ का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था।
- सुभाष चंद्र बोस पैनल वालों ने हार के डर से हंगामा किया।

सुभाष चंद्र बोस पैनल के तर्क

- पैनल के सुभाष वर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाए कि जारी मतदाता सूची में मृत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का नाम शामिल किया था। गैर और बाहरी कर्मचारी भी शामिल किए थे जो मतदान के लिए योग्य नहीं हैं।
- मतदाता सूची कार्यालय समय के बाद प्रकाशित की, उसके बाद दो दिन तक लगातार अवकाश रहा था।
- मतदाता सूची का मिलान काटी गई रसीद से नहीं हो रहा है।
- कुली व संसदीय कार्य विभाग के कर्मचारियों को मतदाता सूची में रखा।

राज्य ओपन के माध्यम से होंगी नवमीं-ग्यारहवीं की परीक्षाएं

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।

10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले कक्षा नवमीं-ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं 12 अप्रैल से शुरू होंगी। यह परीक्षाएं राज्य ओपन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएंगी। वही दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षा को लेकर आवश्यक तैयारियों के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर ही कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं आयोजित होंगी। इस परीक्षा में पूरी तरह पारदर्शिता बरतने के लिए कहा गया है। इसकी जवाबदारी संबंधित स्कूल के प्राचार्य की होगी। राज्य ओपन बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षाओं को लेकर छात्र-छात्राओं को अवगत कराया जाए ताकि छात्र परीक्षा से वंचित न रहें। बताया जाता है 9वीं के साथ-साथ 11वीं कक्षा की परीक्षा हिंदी विषय के पेपर के साथ आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे की पाली में आयोजित होगी।

विद्यार्थियों का मांगा ब्योरा:
परीक्षाओं को लेकर राज्य ओपन बोर्ड ने जिले से छात्र-छात्राओं की



जानकारी मांगी गई है। ताकि छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जा सकें। प्रश्न पत्रों का निर्माण कर इसे समन्वय संस्था अथवा उत्कृष्ट मॉडल स्कूल के माध्यम से इनका वितरण किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में बैठक व्यवस्था को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इस मामले पर विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है।

“ नवमीं एवं ग्यारहवीं की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र राज्य ओपन बोर्ड द्वारा तैयार किए जाएंगे। परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होंगी। इस संबंध में विद्यार्थियों को व्यापक स्तर पर जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

— केके द्विवेदी
संचालक लोक शिक्षण



उल्टी गंगा • बीआरसीसी के आगे सब बौने, डीईओ-डीपीसी और डाइट को नहीं दी जांच रिपोर्ट

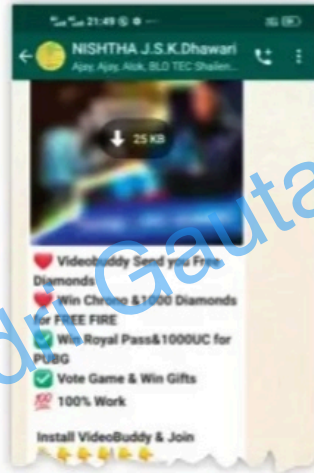
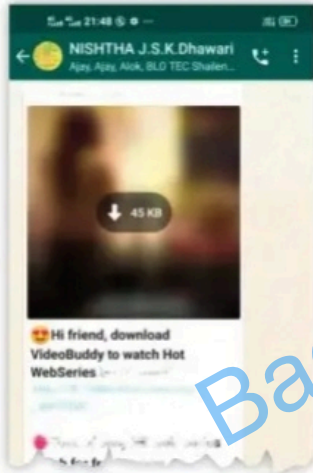
शिक्षिका की हरकत से 'निष्ठा' शर्मसार : वॉट्सएप ग्रुप में 11 पोर्न वीडियो का मामला दबाने गजब की गिरोहबंदी!

भारत न्यूज | सतना

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शासकीय हाईस्कूल की एक शिक्षिका की शर्मसार करती हरकत के अक्षम्य गुनाह को दबाने के लिए यहां के शिक्षा विभाग में गजब की गिरोहबंदी का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। गिरोहबंदी इतनी शांति है कि डीईओ और डाइट प्राचार्य से लेकर डीपीसी तक महज एक बीआरसीसी के आगे बौने पड़ गए हैं।

मगर, नहीं मिली जांच रिपोर्ट

इन अफसरों को सोहावल के बीआरसीसी एसबी सिंह ने 10 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। बीआरसीसी ने बताया कि उन्होंने आरोपी शिक्षिका के स्कूल से संबंधित संकुल की प्राचार्य को रिपोर्ट सौंप दी है। जबकि बीआरसीसी को इस मामले की जांच के आदेश डाइट के प्राचार्य नीरव दीक्षित ने दिए थे। डाइट प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि जांच प्रतिवेदन उन्हें नहीं मिला है। आरोप है कि बीआरसीसी ने डीईओ डॉ. एसएन पांडेय से भी तथ्य छिपा रखे हैं। इस मसले पर डीपीसी सुशील श्रीवास्तव का भी कमोवेश यही हाल है।



क्या है पूरा मामला

ऑनलाइन शैक्षणिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निष्ठा नाम से अकादमिक प्रोग्राम संचालित है। इसके तहत जनशिक्षा केंद्र स्तर पर वॉट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। वॉट्सएप के ग्रुप एडमिन जन शिक्षक हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को सुबह पौने 8 बजे जनशिक्षा केंद्र कन्या धवारी के निष्ठा वॉट्सएप के ग्रुप को लेकर तब हालात हंगामाई हो गए जब ग्रुप मेंबर और हाईस्कूल की एक बहुचर्चित शिक्षिका ने एक के बाद एक महज 6 मिनट

के अंदर पोर्न वीडियो के 11 लिंक पोस्ट कर दिए। जब यह शर्मनाक हरकत हुई ग्रुप में 256 मेंबर थे। जिनमें अकेले 70 फीसदी शिक्षिकाएं जुड़ी हुई थीं। देखते ही देखते 63 मेंबर ने ग्रुप छोड़ दिया। बात बिगड़ती देख ग्रुप एडमिन और जनशिक्षक धर्मेन्द्र सेन ने 78 अन्य मेंबरस को ग्रुप से रिमूव कर दिया मगर दिलचस्प यह रहा कि उस शिक्षिका को आंच तक नहीं आई जिसने स्टडी मैटेरियल के नाम पर पोर्न वीडियो अपलोड किए थे। हंगामा और बढ़ा तो धर्मेन्द्र ने ग्रुप को ही डिजाल्व कर दिया।

शुरु हो गया खेल • सवाल किसी से, जवाब किसी का

ऑनलाइन अकादमिक प्रोग्राम में इस नीच हरकत से नाराज डाइट के प्राचार्य नीरव दीक्षित ने सोहावल जनपद के बीआरसीसी एसबी सिंह को मामले की जांच के निर्देश दिए। बीआरसीसी ने 12 मार्च कन्या धवारी के जनशिक्षक धर्मेन्द्र सेन को नोटिस (पत्र क्रमांक 400) देकर आरोपी शिक्षिका के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन मांगा, मगर इससे पहले कि जनशिक्षक का जवाब आता कन्या धवारी के प्राचार्य और जन शिक्षा केंद्र के प्रभारी सुभाष मिश्रा बीच में कूद पड़े। उन्होंने आरोपी शिक्षिका और ग्रुप एडमिन का बचाव करते हुए आनन फानन में 17 मार्च को बीआरसीसी के समक्ष (पत्र क्रमांक/361) जवाब दाखिल कर दिया। और, इस तरह वक्त गुजरा, बात ठंडे बस्ते में बंद हो गई।

इनका कहना है



बीआरसीसी ने मैरिक्क बताया है कि जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन जांच प्रतिवेदन अभी हमें मिला नहीं है।
नीरव दीक्षित,
प्राचार्य डाइट



जांच रिपोर्ट संकुल प्राचार्य (एसएलबी) को सौंप दी गई है, मैरिक्क तौर पर डीईओ, डाइट प्राचार्य और डीपीसी को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।
एसबी सिंह, बीआरसीसी सोहावल



बीआरसीसी को कार्रवाही के निर्देश दिए गए हैं। मगर अभी हमें रिपोर्ट नहीं मिली है।
सुशील श्रीवास्तव,
डीपीसी

अजा वर्ग के छात्रों को कोचिंग कराएगी सरकार

भोपाल। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों का इंजीनियर, डॉक्टर, जज और वकील बनने का सपना राज्य सरकार पूरा करेगी। उन्हें आकांक्षा योजना के तहत प्रदेश के चुनींदा कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलवाकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए इस वर्ग के इच्छुक विद्यार्थियों से 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। आइआइटी, जेइइ, नीट व क्लैट की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान में दाखिला कुछ मापदंडों पर मिलेगा। पहला तो वर्ष 2020 में विद्यार्थी ने हाईस्कूल परीक्षा 60 फीसद अंक से उत्तीर्ण की हो और इस साल 11वीं की परीक्षा दे रहा हो। साथ ही उसके अभिभावक की सालाना आय छह लाख रुपये से ज्यादा न हो। इसे लेकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन भी जारी किया है। -ब्यूरो

स्नातक परीक्षा पर शीघ्र होगा निर्णय

परीक्षा से जुड़ी विद्यार्थियों की समस्याओं पर अतिरिक्त संचालक डा. सिलावट ने दिया मार्गदर्शन



इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या शहर में फिर तेजी से बढ़ने लगी है। ऐसे में परीक्षा करवाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। अप्रैल से शुरू होने वाली स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षा पर उच्च शिक्षा विभाग मंथन कर रहा है। संभवतः अगले 36 घंटे में परीक्षा के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। विद्यार्थी परीक्षा का तैयारियों पर ध्यान दें।

ये बातें उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक प्रो. सुरेश सिलावट ने कही। उन्होंने मंगलवार शाम 'हेलो नईदुनिया' कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों के परीक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन परीक्षा से छात्रों को लाभ मिलेगा। इससे उनका सही ढंग से आकलन व मूल्यांकन होगा जिससे भविष्य में अच्छी कंपनी में आसानी से प्लेसमेंट हो सकेगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश मिल सकेगा।

जितना पाठ्यक्रम पढ़ाया है, उसमें से ही पूछा जाएगा

संक्रमण की वजह से महाविद्यालयों में भले ही आनलाइन पढ़ाई हुई है, लेकिन पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में परीक्षा में सभी इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएंगे क्या? -करण पटेल, महु

- जनवरी से आनलाइन के अलावा ऑफलाइन कक्षाएं भी महाविद्यालयों में लगाई गई हैं जिससे पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके। वैसे कोरोना संक्रमण के कारण सत्र कम अवधि का रहा है। इसलिए जितना पाठ्यक्रम शिक्षकों ने पुरा करवाया है, उतना ही परीक्षा में पूछा जाएगा। विभाग ने इसके वार में पहले ही विश्वविद्यालय को निर्देश दे रखे हैं।

स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा अगले माह होनी है, लेकिन अभी तक परीक्षा करवाने की पद्धति तय नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अन्य शहरों में रहने वाले विद्यार्थी केंद्रों तक कैसे पहुंचेंगे? -आंचल पाटीदार, मनावर

- ऑफलाइन व ऑपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग मंथन कर रहा है। अगले दो दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लगातार विभागीय मुख्यालय के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। वैसे सामान्य पद्धति से परीक्षा पर जोर दिया जा



डा. सुरेश सिलावट। ● नईदुनिया रहा है।

विधि पाठ्यक्रम की परीक्षा किस प्रकार करवाई जाएगी? विद्यार्थी असमंजस में हैं। -केशव पटेल, वेणव महाविद्यालय

- वार काउंसिल आफ इंडिया (वीसीआइ) ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि विधि पाठ्यक्रम में न जनरल प्रमोशन दिया जाएगा और न ऑपन बुक पद्धति से परीक्षा होगी। पिछली वार की तरह इस वार भी विश्वविद्यालय आनलाइन परीक्षा ले सकता है। हालांकि एलएलबी,

एलएलएम सहित अन्य विधि पाठ्यक्रमों की परीक्षा को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जल्द ही निर्णय लेगा। इसके लिए अभी आदेश आना बाकी है।

संक्रमण बढ़ने से परीक्षाएं ऑपन बुक पद्धति से करवाई जाना चाहिए। ताकि छात्राग्रण : छात्राएं संकमित होने से बच सकें। -आदिल खान, सतवास

- संक्रमण बढ़ने से डीएवीवी और उच्च शिक्षा विभाग को भी विद्यार्थियों की चिंता है। साथ ही उनके भविष्य के लिए परीक्षा करवाने को लेकर मंथन चल रहा है। ऑपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया है। विभाग अभी कई विकल्पों पर विचार-विमर्श कर रहा है। गुरुवार तक स्थिति स्पष्ट होगी।

परीक्षा में पूरा पाठ्यक्रम पूछा जाएगा क्या? -शिवम भवसर

- परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तैयार हो चुके हैं। वैसे महाविद्यालयों में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नपत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा पाठ्यक्रम जरूर कम किया गया है, लेकिन विद्यार्थियों को सभी इकाइयों की पढ़ाई करने पर ध्यान देना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता शिविर में प्रदेश का नेतृत्व करेंगी नूपुर

भोपाल । भारत सरकार युवा कार्यक्रम
एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा



नूपुर

योजना क्षेत्रीय
निदेशालय
गुवाहाटी, असम
द्वारा अगस्तला
में आयोजित
राष्ट्रीय एकता

शिविर में शासकीय
गीतांजलि कन्या स्नाकोत्तर (स्वशासी)
महाविद्यालय कि छात्रा कुमारी नूपुर
सौंधिया का चयन हुआ है । नूपुर संपूर्ण
मध्यप्रदेश (राष्ट्रीय सेवा योजना) का
नेतृत्व त्रिपुरा (अगस्तला) में 28 मार्च
तक चलने वाले कार्यक्रम में करेंगी ।
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ.अलका
डेविड और राष्ट्रीय सेवा योजना के
कार्यक्रम अधिकारी डॉ.आरधना वर्मा
और डॉ.प्रतीक्षा सांवले एवं प्राध्यापकों ने
नूपुर को शुभकामनाएं दी हैं । -(नरि)

स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा आफलाइन और पहले-दूसरे वर्ष की ओपन बुक पद्धति से संभव

कपिलनील • इंदौर

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अगले माह होने वाली स्नातक परीक्षाओं को लेकर अस्मंजस है। आफलाइन का विरोध कर रहे विद्यार्थी ओपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाने पर अड़े हैं। लगातार प्रदर्शन व धरनों के कारण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने परीक्षा संचालित करने पर उच्च शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा है, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। विभागीय सूत्रों के अनुसार वीए, वीकाम व वीएससी अंतिम वर्ष की आफलाइन परीक्षा ही करवाई जा सकती है। प्रथम-द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए विकल्प खोजे जा रहे हैं। बताया जाता है कि ओपन बुक पद्धति के अलावा जनरल प्रमोशन पर भी विचार किया जा रहा है।

फरवरी में विभाग के आदेश पर विवि ने वीए, वीकाम, वीएससी सहित अन्य स्नातक कक्षाओं की आफलाइन परीक्षा 1 अप्रैल से 15 मई के बीच रखी है। विरोध के बीच अब विवि ने विभाग को पत्र लिखकर लगातार हो रहे प्रदर्शन और धरना आंदोलनों से अवगत कराया है। इस बीच अतिरिक्त संचालक डा. सुरेश सिलावट ने विभाग को पत्र लिखकर परीक्षा करवाने के सुझाव दिए हैं। इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा आफलाइन और प्रथम-द्वितीय वर्ष की परीक्षा ओपन बुक पद्धति से लेने के बारे में बताया है। इस सुझाव पर विवि भी सहमत है। विवि के अधिकारियों का तर्क है कि विद्यार्थियों के लिए अंतिम वर्ष काफी महत्वपूर्ण



शेष विश्वविद्यालयों की ओर से आवेदन नहीं

प्रदेशभर में तीन शहरों इंदौर, भीमाल व जबलपुर में संक्रमण बढ़ा है। केवल देवी अहिल्या विवि की आफलाइन परीक्षा को लेकर विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर अधिकारियों ने परीक्षा पर विभाग से राय मांगी है। उच्च शिक्षा विभाग को शेष किसी भी विवि से ओपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाने को लेकर कोई आवेदन नहीं मिला है। यही कारण है कि विभाग को परीक्षा पर निर्णय लेने में समय लग रहा है।

परीक्षा का विरोध तेज, भूख हड़ताल और प्रदर्शन

आफलाइन परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों को विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को देवी अहिल्या विवि में काफी हलचल रही। छात्र नेता जावेद खान और कुछ विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं भाराछास के छात्र नेता विकास नंदवाना ने ओपन बुक पद्धति के लिए जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। उधर कुलपति ने कहा कि 36 घंटे में परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

होता है। इस दृष्टि से आफलाइन परीक्षा जरूरी है जिससे फाइनल प्लेसमेंट व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आसानी से प्रवेश मिल सके। प्रथम-द्वितीय वर्ष में ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराई जा सकती है या जनरल प्रमोशन दे सकते हैं।

इन पर विभाग में मंथन शुरू हो चुका है। इस कारण परीक्षाओं पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि गुरुवार तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद

है। परीक्षा नियंत्रक डा. अशेष तिवारी का कहना है उच्च शिक्षा विभाग को परीक्षा से जुड़ी परिस्थितियों से अवगत करा दिया है। वैसे विवि आफलाइन और ओपन बुक पद्धति दोनों से परीक्षा करवाने को तैयार है। डा. सिलावट का कहना है मंगलवार को विभाग मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक हुई थी, पर निर्णय नहीं हुआ है। संभवतः गुरुवार तक आदेश आ सकता है।

पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट के आधार पर होगा मूल्यांकन

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार ने कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल की तरह इस बार भी जनरल प्रमोशन देने की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में पहली से आठवीं तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई थीं। इस दौरान हर विषय में 40 अंक का प्रोजेक्ट वर्क जोड़ा गया था, जिसे बच्चों को घर वालों की मदद से तैयार करना था। इसी प्रोजेक्ट के आधार पर मूल्यांकन कर उनका रिजल्ट तैयार होगा। इसमें 60 अंक वह भी जुड़ेंगे जो ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान कराई गई पढ़ाई के अनुसार दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल 100 अंकों में से रिजल्ट तैयार होगा।

इसके साथ ही नौवीं व द्वादशवीं की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा

प्राचार्य के खिलाफ एकजुट हुई शिक्षिकाएं, किया घेराव

भोपाल। प्रोफेसर कॉलोनी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विद्या विहार की करीब 25 शिक्षिकाएं मंगलवार सुकृ संकुल केंद्र शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में धरन पर बैठ गईं। ये सभी संकुल प्राचार्य से न्याय देने की मांग करते हुए संकुल केंद्र के हॉल में जाकर दो घंटे बैठी रहीं। शिक्षिकाओं का कहना था कि उनके स्कूल की प्राचार्य उन्हें छात्रावास में जाकर पढ़ाने का दबाव डाल रही हैं, जबकि

कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण अभी शासन की ओर से 31 मार्च तक स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बंद किया है। संकुल प्राचार्य ने शिक्षिकाओं से कहा कि वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हैं। इसके बाद सभी शिक्षिकाएं जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। शिक्षिकाओं द्वारा हंगामे के बाद डीईओ नितिन सक्सेना कार्यालय से बाहर आए और उन्होंने शिक्षिकाओं को समझाकर भेजा दिया।

के लिए समयसारिणी भी जारी कर दी है। नौवीं व द्वादशवीं की वार्षिक परीक्षा 12 अप्रैल से शुरू होंगी। मंत्री का कहना है कि अभी वार्षिक परीक्षा ऑफलाइन लेने की तैयारी है। अगर कोरोना का प्रभाव बढ़ेगा तो परीक्षा ऑनलाइन भी ली जा सकती है।



किसी भी कक्षा में बच्चों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के आधार पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। प्रोजेक्ट के आधार पर मूल्यांकन होगा। **इंदर सिंह परमार**, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री

खाली रही सीटें प्राचार्य अपने स्तर पर भरेंगे

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली सीटों को प्राचार्य भर सकेंगे। सरकार उन्हें इसके लिए अधिकृत कर रही है। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही। वे मंगलवार को मंत्रालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नजदीक के महाविद्यालय में वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।



उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी दस्तावेजों को ऑनलाइन स्कैन कर लिया जाए, ताकि उन्हें महाविद्यालयों में सत्यापन के लिए बार-बार दस्तावेज नहीं ले जाना पड़ें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जारी जाति प्रमाण पत्रों को स्कैन करने की

जरूरत नहीं होगी। यदि विद्यार्थी एक बार नामांकन करा लें, तो दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए दोबारा नामांकन की जरूरत नहीं होगी। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों में संशोधन पर भी चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित विद्वानों ने इस संबंध में सुझाव दिए। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन सहित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी एवं निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य और संचालक उपस्थित थे।

सरकार की बड़ी घोषणा
करमुक्त पीएफ सीमा बढ़ाकर
पांच लाख रुपए की गई
नई दिल्ली | वित्त विधेयक
(बजट)-2021 मंगलवार
को लोकसभा से पास हो
गया है। इसमें सरकार ने
कुछ संशोधन किए हैं। इसके
मुताबिक अब भविष्य निधि
(पीएफ) में पांच लाख रुपए
तक के निवेश पर ब्याज में छूट
मिलेगी। यानी ब्याजमुक्त पीएफ
निवेश की सीमा बढ़ाई गई है।
हालांकि छूट सिर्फ उन्हें मिलेगी,
जिन्हें नियोक्ता की ओर से पीएफ
में योगदान नहीं मिलता।

परीक्षाओं से पहले एक-एक कक्षा के साथ पूरे स्कूल की बिल्डिंग को किया जाएगा सेनिटाइज

10वीं-12वीं के प्री-बोर्ड एजाम और 9वीं-11वीं की मुख्य परीक्षाएँ 12 अप्रैल से

हमारे प्रतिनिधि | जबलपुर

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएँ और 9वीं-11वीं की मुख्य परीक्षाएँ 12 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने पूरी कार्ययोजना बना ली है। परीक्षाओं के दौरान

कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। स्कूल की एक-एक कक्षा सहित पूरी बिल्डिंग सेनिटाइज होगी। प्रवेश द्वार पर छात्रों की थर्मल

स्कैनिंग के जरिए चैकिंग होगी। परीक्षाओं व प्रैक्टिकल में छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। हालाँकि सूत्र कोरोना की वजह से बदले माहौल को देखते हुए परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव की बात भी कह रहे हैं। आगे शासन का निर्णय चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल शिक्षा अधिकारी तय तारीख के मुताबिक ही परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पी-4



ऐसे हो रहा अध्यापन

- » ऑनलाइन विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
- » फोन पर भी शिक्षक विद्यार्थियों-अभिभावकों से चर्चा कर मार्गदर्शन दे रहे हैं।
- » विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक के पुराने पेपर हल करने कहा जा रहा है।
- » अब तक जो पढ़ाया गया है उसे ही बार-बार दोहराने की बात की जा रही है।

प्री-बोर्ड और दसवीं-ब्यारहवीं की मुख्य परीक्षाओं के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कक्षाओं-स्कूल भवन को सेनिटाइज किया जाएगा। विद्यार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन परीक्षा-प्रैक्टिकल के दौरान किया जाएगा।

-घनश्याम सोनी, डीईओ

छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे विद्यार्थी

मार्च माह खत्म होने को है और अब तक सभी पात्र विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई है। स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों के प्रोफाइल अपडेशन न करने के कारण ये समस्या आ रही है। कक्षा पहली से आठवीं तक के

विद्यार्थियों की ऑखें तो छात्रवृत्ति का इंतजार कर धक चुकी हैं। इधर शिक्षण सत्र समाप्त की ओर है। यहाँ बता दें कि गत 26 फरवरी को शासन द्वारा कक्षा नवमी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को वन क्लिक

के माध्यम से छात्रवृत्ति जारी की गई थी। इसमें सिर्फ 40 फीसदी विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति पहुँची थी। बाकि 60 प्रतिशत छात्र अब भी छात्रवृत्ति की राह देख रहे हैं। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण ने गत दिवस प्रदेश के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की छात्रवृत्ति व अन्य मुद्दों पर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में उन्होंने छात्रवृत्ति में हीला हवाली पर नाराजगी जाहिर की है।

इधर शिक्षण सत्र खत्म होने को है

कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षाएँ कराने की विद्यार्थी कर रहे माँग

हमारे प्रतिनिधि | जबलपुर | कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान 31 मार्च तक बंद हैं, लेकिन परीक्षाएँ नजदीक आती जा रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों ने ऑनलाइन या फिर ओपन बुक माध्यम से परीक्षाएँ कराने की माँग तेज कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालय समेत विभिन्न कॉलेजों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। एनएसयूआई ने रादुविवि में धरना दिया। धरना प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ गौतम एवं जिला महासचिव मोहम्मद अली के नेतृत्व में दिया गया। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष विजय रजक, कौशल यादव, करन तामसेतवार, नीलेश माहर आदि मौजूद रहे।



साइंस कॉलेज में प्राचार्य से मिले विद्यार्थी | इधर साइंस कॉलेज में समस्त छात्र व छात्राएँ एकत्र होकर प्राचार्य से मिले और बताया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की समयसारिणी घोषित कर दी गई है। ऑफलाइन परीक्षाएँ कराने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। ऑनलाइन परीक्षाएँ कराना ही बेहतर होगा। इस दौरान रोशन सिंह, हिमांशु गुप्ता, आदित्य अक्स्थी आदि मौजूद रहे। पी-2

होमसाइंस कॉलेज में चल रहे प्रैक्टिकल | होमसाइंस महाविद्यालय में विगत दिवस कुछ छात्राएँ कोरोना पॉजिटिव पाई गईं, जिसके बाद कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षाएँ आयोजित कराने एनएसयूआई छात्रा इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मदन महल थाना प्रभारी को सौंपा। इस दौरान अंजलि त्रिवेदी, खुशी त्रिवेदी, स्नेहा सिंग, सौम्या, संध्या पटेल, आदि मौजूद रहीं।

बैंकफुट पर शिक्षा विभाग नहीं मिलेगा 65 हजार विद्यार्थियों को स्वल्पाहार सिर्फ 3 दिन ही हो सका खाद्य सामग्री का वितरण



फैक्ट फाइल

शासकीय स्कूलों में
अध्ययनरत छात्र

| | |
|-------------|-------|
| कक्षा 9वीं | 29547 |
| कक्षा 10वीं | 19175 |
| कक्षा 11वीं | 10447 |
| कक्षा 12वीं | 6488 |

भास्कर न्यूज़ | सतना

हाईस्कूल एवं हायर सेकेंड्री विद्यालयों में इस समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लगातार 8 घंटे छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चे सुबह बिना खाना खाए, स्कूल पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए 19 मार्च को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने जिले के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को स्वल्पाहार देने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद प्राचार्यों द्वारा सिर्फ 3 दिन ही विद्यार्थियों को स्वल्पाहार वितरित किया गया और 22 तारीख को विभाग ने अपना ही आदेश निरस्त कर दिया। लिहाजा 23 मार्च से छात्रों को स्वल्पाहार के तौर पर मिलने वाली सौगात एक झटके में बंद हो गई। इस सम्बंध में कई प्राचार्यों ने बताया कि स्वल्पाहार के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बजट देने की बात कही गई थी। बजट तो नहीं आया, लेकिन आदेश के पालन में स्थानीय मद से स्वल्पाहार देने के लिए सामग्री क्रय की गई। इस आदेश के निरस्त होने का कारण भी बजट बताया जा रहा है।

नहीं है शाला विकास शुल्क का प्रावधान

विद्यालय के प्राचार्यों द्वारा बताया गया कि आदेश में कहा गया था कि जब तक राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक शाला विकास मद से स्वल्पाहार की व्यवस्था की जाए। जबकि शाला विकास शुल्क विद्यालयों में लेना प्रतिबंधित है। विद्यालय के खर्चों के लिए शासन स्तर पर एसएमडीसी (शाला प्रबंध समिति) के खाते में हर वर्ष एक लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसी राशि से विद्यालय का मेंटीनेंस एवं अन्य खर्च किए जाते हैं।

बढ़ी थी छात्र संख्या

बताया गया कि ग्रामीण स्कूल हों या फिर शहर के स्कूल स्वल्पाहार की व्यवस्था के बाद बीते दिन आम दिनों की तुलना में छात्र संख्या अधिक रही। आमतौर पर 25 प्रतिशत छात्र स्कूलों में आते हैं। आदेश के निरस्त होने के बाद छात्रों की उपस्थिति में गिरावट आने की आशंका भी प्राचार्य व्यक्त कर रहे हैं।

काम धेले का नहीं और पगार हजारों में

जबलपुर| जिले में जितने भी प्रोढ़ शिक्षा कार्यालय चल रहे हैं उनमें काम सीमित है जबकि अन्य विभागों के कर्मचारी-अधिकारियों की यहीं प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने बताया कि दूसरी तरफ मूल विभाग में कामकाज मुश्किल से हो पा रहा है। वैसे भी प्रदेश शासन की तरफ से प्रोढ़ शिक्षा के माध्यम से किसी भी प्रकार की योजना नहीं चल रही है, जिससे इन अधिकारियों-कर्मचारियों की योग्यता का प्रोढ़ शिक्षा कार्यालयों में कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। संघ के रॉबर्ट मार्टिन, मीनूकांत शर्मा, एनोज विक्टर, जियाउर्रहीम, राकेश श्रीवास ने ऐसे स्टाफ को शीघ्र मूल विभाग में वापस भेजने की माँग की है।



बीआरसी पर कार्रवाई की जाए- मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का कहना है कि अध्यापक संवर्ग लोक सेवकों को छठवें वेतनमान की तृतीय किस्त का भुगतान 31 मार्च 2021 तक किये जाने के निर्देश हैं, किन्तु जिला व जनपद शिक्षा केन्द्रों में नियुक्त बीएसी एवं सीएसी (जन शिक्षकों) को छठवें वेतनमान की तृतीय किस्त का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। संघ के मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, नितिन अग्रवाल, महेश कोरी, श्याम नारायण तिवारी आदि ने कलेक्टर से कार्यवाही की माँग की है।

अनुकंपा नियुक्ति में देरी न्याय संगत नहीं-

मप्र शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया का कहना है कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति व जीपीएफ, बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे अन्य लाभ के लिए अनावश्यक रूप से भटकना पड़ता है। संघ के संजय उपाध्याय, रविन्द्र गुप्ता, मदन मनिहार, किशन विश्वकर्मा, तीरथ साहू ने ऐसे मामलों को शीघ्र निराकृत करने की माँग की है।

सरकारी स्कूल में गंदगी देख भड़कीं स्कूल शिक्षा विभाग की पीएस, प्राचार्य को नोटिस

हरिमूमि न्यूज ►► भोपाल

कोरोना से बचाव के जन-जागरुकता अभियान के लिए राजधानी के बागसेवनियां क्षेत्र पहुंची स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव से स्कूल चलने का आग्रह करना एक सरकारी स्कूल प्राचार्य को भारी पड़ गया। प्राचार्य के आग्रह के बाद स्कूल पहुंची पीएस ने जब स्कूल परिसर और कमरों में गंदगी देखी तो वह भड़क गई और उन्होंने प्राचार्य को जमकर फटकार लगाई। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी जन-जागरुकता अभियान के तहत बागसेवनियां क्षेत्र में जन-सामान्य को कोरोना से बचाव के लिए मास्क बांटने और जागरुक करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने लोगों से कहा कि

➤ इधर, कियावत ने लोगों को किया जागरुक

लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त जयश्री कियावत द्वारा गुलमुहोर क्षेत्र में मास्क बांटे गए और लोगों को सतर्कता के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने की समझाइश दी।

कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता की जरूरत है। इस दौरान बागसेवनियां क्षेत्र स्थित शासकीय नवीन उमा विद्यालय की प्राचार्य शिक्षा यादव ने पीएस शमी से स्कूल भ्रमण आग्रह किया और पीएस स्कूल पहुंच गई, लेकिन इस दौरान स्कूल परिसर में गंदगी नजर आई और उन्होंने प्राचार्य को फटकार लगाते हुए बेहतर सफाई रखने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि मामले में प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मार्शल आर्ट का दिया प्रशिक्षण

कला व वाणिज्य कॉलेज में छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर



हरिभूमि न्यूज ►► भोपाल

शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय में छात्राओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट से सुरक्षा के गुर सिखाए गए।

क्रीडाधिकारी डॉ. रश्मि केला होलानी ने बताया कि शिविर में चंद्रवंशी, डॉ. राजीव चौबे ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाण-पत्र एवं शील्ड प्रदान की गई। डॉ. रश्मि ने सभी का आभार माना।

विश्वविद्यालय में 54 लाख 49 हजार घाटे का बजट पेश

पिछले साल की अपेक्षा घाटे में करीब साढ़े 6 करोड़ की गिरावट

जागरण, रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में मंगलवार को कार्यपरिषद की बैठक हुई। बैठक में विश्वविद्यालय का सालाना बजट अनुमोदित किया गया। बैठक में विश्वविद्यालय ने 54 लाख 49 हजार घाटे का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल की तुलना में करीब साढ़े 6 करोड़ कम घाटे का रहा। बता दें कि गत वर्ष विश्वविद्यालय ने 7 करोड़ 31 लाख रूपये घाटे का बजट पेश किया था, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय के वित्त विभाग ने कई गैर जरूरी खर्चों में कटौती कर दी। ऐसे कार्य जिनके लिए सालाना बजट आवंटित होता रहा परंतु उसका उपयोग नहीं होता था, ऐसे खर्चों में कटौती कर विश्वविद्यालय ने घाटे की राशि को काफी कर दिया। मंगलवार को पेश बजट में विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 की अनुमानित आय 72 करोड़ 90 लाख 50 हजार रूपये पटल पर रखी। वहीं व्यय 73 करोड़ 44 लाख 39 हजार रूपये दर्शाया। विश्वविद्यालय के इस बजट को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने मान्य किया। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की यह बैठक कुलपति प्रो. राजकुमार आचार्य की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कार्यपरिषद सदस्य डॉ. केके त्रिपाठी, सरोज गुर्जर, एडी रीवा डॉ. पंकज श्रीवास्तव, संचिता सरवटे, डॉ. अतुल पाण्डेय, जेडी कोष एवं लेखा आरके प्रजापति, कुलसचिव लालसाहब सिंह व वित्त नियंत्रक प्रवीण सिंह उपस्थित रहे।

त्यौंथर महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने की मांग

कार्यपरिषद सदस्य डॉ. केके त्रिपाठी ने विगत 30 दिसम्बर 2020 की कार्यपरिषद बैठक का पालन प्रतिवेदन अंगीकृत करने से इंकार कर दिया। इस बैठक में अतिथि विद्वानों के मानदेय को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें हुए निर्णय पर कार्यवाही नहीं करने पर वित्त अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उक्त कार्यवाही न होने पर कार्यपरिषद सदस्य ने आपत्ति जाहिर की। साथ ही, परीक्षा केंद्र निर्धारण संबंधी चर्चा के



कन्या छात्रावास के पास थाना भवन का विरोध

विश्वविद्यालय ने हाल ही में खेल एवं युवक कल्याण विभाग को बेशकीमती जमीन उपयोग के लिए दे दी, जिसकी सूचना मंगलवार को कार्यपरिषद ने ग्रहण की। विश्वविद्यालय की एक और जमीन पर पुलिस विभाग ने नजर गड़ा रखी है। विश्वविद्यालय थाना हेतु कन्या छात्रावास के पास जमीन लेने पर पुलिस विभाग अड़ा हुआ है। जबकि कार्यपरिषद सदस्यों से लेकर अन्तः शिक्षकगण इसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। मंगलवार को कार्यपरिषद सदस्यों ने कन्या छात्रावास के समीप थाना भवन का विरोध जताया, जिस पर समिति गठित करने का अनुमोदन बैठक में किया गया। वरिष्ठ आचार्य के संयोजकत्व में गठित होने वाली समिति की अनुशंसा पर अब आगामी कार्यवाही होगी।

दौरान उन्होंने शासकीय त्यौंथर महाविद्यालय को पुनः परीक्षा केंद्र बनाने की मांग उठाई। पूर्व में मप्र उच्च न्यायालय के आदेश पर उक्त महाविद्यालय का केंद्र तोड़ा गया था। तब इस महाविद्यालय में नियमित शिक्षक नहीं रहे और अब 15 नियमित शिक्षकों की पदस्थापना हो चुकी है। इस लिहाज से त्यौंथर महाविद्यालय को केंद्र बनाने की मांग उठाई गई, जिस पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विचार किया जायेगा। शेष केंद्रों के निर्धारण की सूचना बैठक में ग्रहित की गई।

डिजिटल मोड में होंगी दुर्लभ पुस्तकें

बैठक में परीक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अभिलेखों, केंद्रीय पुस्तकालय की दुर्लभ पुस्तकों तथा अन्य विभाग के पुराने अभिलेखों को डिजिटल मोड में करने का अनुमोदन किया गया। यूजीसी द्वारा देय राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को वर्ष 2007 से 2015 तक आरक्षित वर्ग के शोधार्थियों हेतु 2 करोड़ 70 लाख 97 हजार रूपये प्राप्त हुए। इसमें से 1 करोड़ 22 लाख 81

हजार रूपये विश्वविद्यालय के खाते में शेष रह गए। भविष्य में किसी तरह के पचड़े से बचने के लिए उक्त राशि यूजीसी को वापस लौटाने का निर्णय मंगलवार को बैठक में लिया गया।

निलंबित शिक्षक को किया

जाएगा बहाल

छात्राओं को अश्लील संदेश भेजने के मामले में निलम्बित शिक्षक डॉ. अजय सक्सेना को बहाल करने का निर्णय कार्यपरिषद ने मंगलवार को लिया। मामले की जांच के लिए गठित प्रो. आरएम मिश्रा व डॉ. अतुल पाण्डेय की समिति ने रिपोर्ट में बताया कि गवाही के लिए 18 छात्राओं को बुलाया गया, जिसमें से 16 छात्राएं अनुपस्थित रहीं। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों को आधार बनाकर समिति ने डॉ. सक्सेना का निलम्बन समाप्त करने की अनुशंसा की, जिसे कार्यपरिषद ने मान लिया। कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान करने की बात भी कही।

मप्र में स्कूली बच्चों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन, होगी वार्षिक परीक्षा और मूल्यांकन

हरिभूमि न्यूज ►► भोपाल

मप्र प्रदेश के स्कूलों में इस बार किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 की बकायदा वार्षिक परीक्षाएं होंगी और कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रतिभापर्व व प्रोजेक्ट आधारित वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के मीडिया प्रकोष्ठ ने स्थिति स्पष्ट



करते हुए कहा है कि इस वर्ष किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन देने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं और ना ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव ►► शेष पेज 6 पर

यह है तैयारी

पहली से आठवीं तक में सत्र 2020-21 के लिए अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट/ प्रोजेक्ट आधारित (होम बेस्ड एसाइनमेंट के रूप में) 18-25 फरवरी तथा 8-20 मार्च 2021 के दौरान किया गया। बच्चों ने घर पर रहकर इन वर्कशीट्स व प्रोजेक्ट को पूर्ण कर निर्धारित अवधि में ►► शेष पेज 6 पर

स्कूल शिक्षा विभाग से भुगतान की मांग

ट्रांसफर के बाद आठ महीने से अटका शिक्षकों का वेतन

हरिमूमि न्यूज ►► भोपाल

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बीते एक सालों में किए गए ट्रांसफर अब शिक्षकों के लिए परेशानी बन रहे हैं। विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण तो कर दिए गए हैं, लेकिन कई शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। मप्र शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष भोपाल सुभाष सक्सेना का कहना है कि प्रदेश में विगत 1 वर्ष में जिन शिक्षकों के स्थानांतरण 1 जिले से दूसरे जिले में हुए हैं अथवा



ट्रायबल से स्कूल शिक्षा विभाग में हुए हैं, उन्हें लगभग से 8 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इस

कारण शिक्षकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक कांग्रेस ने स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की है कि शिक्षकों को तत्काल वेतन का भुगतान किया

जाए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के कारण वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिसे जल्द ठीक किया जाएगा।

हाजिरी नहीं लगाने दी तो शिक्षिकाएं पहुंचीं डीईओ ऑफिस, प्राचार्य ने कहा- देर से आई थीं

हरिमूमि न्यूज ►► मोपाल

राजधानी के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित सरकारी विद्या विहार स्कूल प्राचार्य और शिक्षिकाओं के विवाद को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। मंगलवार को 10 बजे स्कूल पहुंची शिक्षिकाओं को प्राचार्य ने रजिस्टर में साइन नहीं करने दिया। जिसके बाद शिक्षिकाएं स्कूल में ही बैठ गईं। कुछ देर बाद शिक्षिकाएं संकुल प्राचार्य और फिर जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना से मिली और शिकायत की। शिक्षिकाओं ने बताया कि जब से शासन के आदेश हुए तब से वह सुबह 9 बजे आकर 5 बजे घर जा रही हैं। सोमवार को प्राचार्य ने कहा कि मंगलवार से सभी टीचर 10 बजे आएँ और हॉस्टल में जाकर छात्राओं को पढ़ाएं। आदेश को लिखित में मांगा, तो प्राचार्य ने मना कर दिया।



► आयुक्त के आदेश का उल्लंघन

इस संबंध में प्राचार्य निशा कामरानी से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती हैं। आयुक्त लोक शिक्षण के आदेश 9 बजे से आने के हैं, लेकिन 10 बजे आकर उस आदेश का उल्लंघन कर रही हैं। स्कूल बंद है और हॉस्टल की छात्राएं पढ़ना चाहती हैं, इसलिए हमने मानवीयता के नाते पढ़ाने के लिए कहा है। वार्डन द्वारा लिखित आदेश मांगने की बात पूरी तरह झूठ है।

आयुष काउंसलिंग में च्वॉइस फीलिंग आज

भोपाल। बीएएमएस,
बीएचएमएस, बीयूएमएस,
बीएनवायएस में प्रवेश के लिए
स्नातक स्तर पर 2020-21 सत्र की
स्टेट नीट आयुष काउंसलिंग में
रिक्त सीटों पर अब चौथे मॉपअप
राउंड में प्रवेश होंगे। 24 मार्च से 26
मार्च तक च्वॉइस फीलिंग व 30
मार्च तक संबंधित आयुष कॉलेजों
में प्रवेश हो सकेंगे।

ओपेन बुक प्रणाली के तहत आगामी परीक्षा कराने की मांग

जागरण, रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में मंगलवार को एनएसयूआई की जिला इकाई ने प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए एनएसयूआई ने ओपेन बुक परीक्षा प्रणाली के तहत आगामी नियमित स्नातक की वार्षिक परीक्षा कराने की मांग उठाई। इस बाबत एनएसयूआई ने कुलपति डॉ राजकुमार आचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि देश-प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है। इस स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित ऑफलाइन परीक्षा का निर्णय उचित नहीं होगा। एनएसयूआई संगठन ने अन्य दूसरे जिलों में भी ओपेन बुक प्रणाली के तहत परीक्षा कराने की मांग उठाई है। इसी क्रम में संगठन की जिला



इकाई ने भी उक्त कार्यवाही मंगलवार को की। इस दरम्यान संगठन के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी, जिला समन्वयक शुभम तिवारी, संजय चौधरी, संदीप पटेल, संजय मिश्रा, सौरभ पाण्डेय, अमन सोंधिया, शिवेंद्र, आदर्श सहित अन्य छात्र उपस्थित रहे।

न्यू साइंस कॉलेज में अराजक तत्व कर रहे उपद्रव

रीवा। शासकीय न्यू साइंस महाविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से अराजक तत्वों द्वारा आये दिन उपद्रव किया जा रहा है। इसमें महाविद्यालय के कुछ छात्र-छात्राएं शामिल हैं। मामले को लेकर कुछ पीड़ित छात्रों ने मंगलवार को कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। जनसुनवाई में कलेक्टर को लिखित शिकायत देते हुए कुछ छात्र व दो छात्राओं को नामजद कराया गया है।

इस शिकायत में पीड़ित छात्रों ने बताया कि अराजक तत्व व छात्राएं नशे की हालत में रहते हैं और महाविद्यालय परिसर में घिनौनी हरकत करने से भी बाज नहीं आते।

जिसका विरोध करने पर उक्त छात्राओं द्वारा अपने साथियों के साथ अन्य छात्रों के साथ हरदिन मारपीट की जाती है। महाविद्यालय की अन्य छात्राओं के साथ भी उक्त नशेड़ी युवक आये दिन अश्लील हरकत करते हैं। शिकायत में छात्रों ने बताया कि मामले की शिकायत कई दफा महाविद्यालय प्रबंधन से की गई लेकिन महाविद्यालय प्राचार्य समेत अन्य शिक्षक पीड़ित छात्रों को चुप करा देते हैं। इतना ही नहीं, आरोपी छात्रों का पक्ष लेते हुए प्राचार्य व अन्य के द्वारा महाविद्यालय से निकाले जाने की धमकी पीड़ित छात्रों को दी जाती है। बताया गया कि अभी कुछ महीने पहले महाविद्यालय परिसर में पुलिस ने ठापामार कार्यवाही की थी। इस दौरान भी उक्त युवक-युवतियों को नशे की हालत में पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद फिर पुलिस ने इनको छोड़ दिया। और अब यह फिर से महाविद्यालय के सामान्य छात्रों को प्रताड़ित करने लगे हैं।

**पीड़ित छात्रों ने
कलेक्टर से की
शिकायत**

जिले को दो छात्रावासों की मिली सौगात

-निज प्रतिनिधि-

गुना। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंगलवार को जिले को दो छात्रावासों की सौगात दी गई है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने छात्रावासों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की सीधा प्रसारण मानस भवन में दिखाया गया। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेन्द्र सिकरवार, हरि सिंह यादव, रमेश मालवीय, कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम, जिंपई सीईओ निलेश परीख एवं अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी मौजूद रहे।

प्रतीक स्वरूप चेक वितरित

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसान योजनांतर्गत लाभांशित



चेक वितरित करते भाजपाजन।

किसानों में गुना जिले के 144532 किसान, ग्रामीण पथ विक्रेताओं में गुना जिले के 4831 ग्रामीण पथ विक्रेता तथा उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्रावासों के लोकार्पण में गुना में 385.37 लाख रुपये की राशि से निर्मित बालक छात्रावास और जाटपुरा परिसर में 386.40 लाख रुपये की लागत से निर्मित 100 सीटर कन्या

छात्रावास शामिल था। इस अवसर पर कीट प्रकोप से फसल क्षति से द्वितीय किश्त की राहत राशि 24.17 करोड़ तथा बाढ़/अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति पर कृषकगण 1.69 करोड़ रुपये की राहत राशि की द्वितीय किश्त से लाभांशित हुए। कार्यक्रम में अतिथिगणों द्वारा लाभांशितों को प्रतीक स्वरूप चेक वितरित किए।

जिम्मेदारों की लापरवाही, छात्र-छात्राओं पर पड़ रही भारी

■ बुधनी विकासखंड की पानगुराड़िया हायर सेकंडरी स्कूल बनी दुदशा का शिकार

■ शिक्षकों का बना हुआ है अभाव, अतिथियों के भरोसे चल रही वलासें

■ शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार नहीं करते कोई कार्रवाई

मध्य स्वदेश ■ सीहोर/रहटी

शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में भले ही सरकार लाख प्रयास करे, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही मुख्यमंत्री के प्रयासों पर भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र एवं बुधनी विकासखंड की पानगुराड़िया सहित अन्य स्कूलों में ही स्थिति यह है कि यहां पर न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं। इसके कारण जहां बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो वहीं उनके पालकों की चिंता भी बढ़ रही है।

बुधनी विकासखंड की पानगुराड़िया स्कूल इन दिनों दुदशा का शिकार हो गई है। यह स्कूल कभी विकासखंड की सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में शुमार थी, लेकिन अब स्कूल अपनी दुदशा पर ही आसू बहा रही



है। दरअसल, स्कूल में न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं। प्राचार्य मधुलिका मिश्रा भी माह में एक-दो बार ही स्कूल आती हैं, जिसके कारण अन्य स्टाफ भी अपनी मनमर्जी से ही स्कूल में आना-जाना करता है।

नहीं है विषय विशेषज्ञ शिक्षक

पानगुराड़िया स्कूल में स्थायी शिक्षक के नाम पर सिर्फ तीन शिक्षक हैं। इसके अलावा 5 अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही शिक्षण कार्य संचालित है। इनमें से एक स्थायी शिक्षिका मंजूलता मेहरा के पास लाइब्रेरी का भी प्रभार है। प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में वे स्कूल की प्रभारी भी

रहती हैं। एक अन्य शिक्षक भी विवादों में बने हुए हैं। उन पर कई तरह के आरोप भी हैं।

लगातार कम हो रही विद्यार्थियों की संख्या

पानगुराड़िया के हायर सेकंडरी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक 167 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की यह संख्या पिछले वर्ष 195 थी और कभी यहां पर 400 से 500 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत थे, लेकिन लगातार स्कूल से बच्चों की संख्या घटती जा रही है। इसका कारण पालक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेश पाठक बताते हैं कि स्कूल का माहौल दिन-प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है।

इनका कहना है

स्कूल में पहले पर्याप्त मात्रा में स्टाफ था, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में यहां पदस्थ शिक्षकों ने अपने-अपने गृह जिलों में तबादले करा लिए, इसके कारण स्कूल में शिक्षकों का अभाव है। मैं भी अस्वस्थता के कारण स्कूल नहीं जा पा रही हूं, मैंने मेडिकल लगाया है।

मधुलिका मिश्रा, प्राचार्या, हायर सेकंडरी स्कूल, पानगुराड़िया

यहां पर जो स्टाफ तैनात है वह बेहद लापरवाह और विवादित है। इस कारण अब माता-पिता भी अपने बच्चों को यहां पढ़ाना नहीं चाहते हैं।

नहीं होते बच्चों के प्रेक्टिकल

स्कूल में इस समय बायो साइंस के कक्षा ग्यारवी में 14 और कक्षा बारहवीं में 30 बच्चे हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियन नहीं होने के कारण बच्चे प्रेक्टिकल नहीं कर पाते हैं। स्कूल में लैब तो बनी है, लेकिन पिछले करीब 2 वर्षों से यहां पर कोई भी लैब टेक्नीशियन की पदस्थापना नहीं हो सकी है। इसके कारण बच्चों का भविष्य भी अधर में ही है।

डीईओ के स्थानांतरण के बाद बंद हो गई जांच

बीआरसी कार्यालय की बाउण्ड्री गिराए जाने का मामला

स्टार समाचार पन्ना

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अधिकारी के स्थानांतरण के बाद सारी व्यवस्थाएं फिर से पहले की तरह हो गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर पुनः कमल सिंह कुशवाहा ने कमान संभाली है और इसके बाद कार्यालय में लंबित जांच की सभी फाइलों को बंद कर रख दिया गया है। गौरतलब है कि जनपद शिक्षा केन्द्र बीआरसी कार्यालय की बाउण्ड्री वाल के बिना सूचना गिराए जाने के मामले में दो दो बार जांच होने के बाद कार्यावाही की बारी आई तो जिला अधिकारी बदल गए। अब पुनः आए अधिकारी की कृपापात्र अधीक्षक को कार्यवाही का कोई डर नहीं है। क्योंकि उन पर कुशवाहा का पूरा संरक्षण है। यही कारण है कि जांच पूरी होने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विदित हो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभिवान के तहत संकुल प्राचार्य मनहर कन्व हायर सेंकेडरी स्कूल एवं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास पन्ना की वार्डन ने अभियान के तहत आर्बिट्र राशि को ठिकाने लगाने के लिए बीआरसी कार्यालय की बनी हुई मजबूत बाउण्डरीवाल को तोड़कर नवीन बाउण्डरी वाल का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया दिया था। वार्डन द्वारा निर्माण के पूर्व न तो बीआरसी प्रभारी से कोई अनुमति ली और न ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। सीधा बजट ठिकाने लगाने की मंशा से बाउण्डरी तोड़कर नवीन निर्माण प्रारंभ कर दिया गया।



शनिवार को बाउण्डरी तोड़ी और रविवार तक नए निर्माण के लिए पिलर भी खोद दिए गए। मामले की जानकारी मिलते ही बीआरसी प्रभारी को मिली तो वह भौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को तत्काल रोकने को कहा। इसके बाद उन्होंने डीपीसी विष्णु त्रिपाठी को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए पत्र भेजा। इसके बाद डीपीसी ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्रवास की वार्डन मनीषा सिंह परमार को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र पन्ना द्वारा अगवत कराया गया है कि आपके द्वारा बीआरसी परिसर की बाउण्डरीवाल को जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया है। जिससे शासकीय सम्पत्ति की क्षति के साथ बीआरसी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बाधित हुई है। शासकीय सम्पत्ति को आपके द्वारा बिना किसी अनुमति के गिराया जाकर शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। उक्त कृत्य

कदाचार की श्रेणी में आजा है। क्यों न आपके विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराते हुए आपके द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। नोटिस में दो दिन के अंदर जबाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। जवाब में वार्डन ने बताया कि 60 मीटर लम्बी बाउण्डरी एक टेक्टर की टोकर के कारण गिरी है। जबाब से संतुष्ट न होते हुए डीपीसी ने कार्यवाही हेतु जिलाध्यक्ष अधिकारी को पत्र भेज दिया।

पांच सदस्यीय दल ने की फिर जांच

डीपीसी द्वारा कार्यवाही हेतु भेजे गए प्रतिवेदन से तत्कालीन डीईओ सचिचतानंद पाण्डेय संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पांच सदस्यीय दल से पुनः जांच कराने के आदेश दिए। इस जांच टीम में डीपीसी विष्णु त्रिपाठी, केके सोनी, भारती श्रीवास्तव एवं राजेन्द्र जैन सहित एक अन्य को शामिल किया गया। इस टीम ने जांच की और बताया कि बिना अनुमति



बाउण्डरी तोड़ी गई, जिसमें करीब 55 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद अब शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में वार्डन व संकुल प्राचार्य के विरुद्ध एफआईआर और नुकसान की भरपाई हेतु वसूली की कार्यवाही की जानी थी। लेकिन डीईओ के स्थानांतरण के बाद सब बंद हो गया। नवागत डीईओ पूरे मामले से अनजान बने हुए हैं और जल्द कार्यवाही की बात कर रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि वार्डन को इन्हीं का संरक्षण रहा है। जिसके चलते उन्हें नियम विरुद्ध प्रभार भी मिली है। ऐसे में वार्डन पर कार्यवाही होना संभव नहीं दिखता। गौरतलब है कि इस कार्यवाही और जांच के फेर में बीआरसी की बाउण्डरी आज भी टूटी पड़ी है। जबकि यहां छत्रवास में अब छत्राएं भी रहने लगीं हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को शावद इससे कोई सरोकार नहीं है।

कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा एक मई से

रीवा(नव स्वदेश)। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा हायर सेकेण्ड्री कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं एक मई से आरंभ हो रही हैं। हायर सेकेण्ड्री की परीक्षा एक मई से 21 मई तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होंगी। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र शुरू होने से 15 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। प्रत्येक परीक्षार्थी का उपस्थिति पत्रक की फोटो से मिलान किया जायेगा। प्रवेश पत्र में भी फोटो लगाना अनिवार्य है। जिला शिक्षा अधिकारी आर.एन. पटेल ने बताया कि कक्षा 12वीं के नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र शनिवार एक मई को विशिष्ट भाषा हिन्दी तथा सामान्य हिन्दी(व्होकेशनल के छात्रों सहित)का होगा। सोमवार 3 मई को विशिष्ट भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा संस्कृत (व्होकेशनल के छात्रों सहित) तथा मंगलवार 4 मई को फिजिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेण्ड्री, पोल्टीफार्मिंग एवं फिसरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास तथा द्वितीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स की परीक्षा होगी। बुधवार 5 मई को विशिष्ट भाषा उर्दू तथा द्वितीय भाषा सामान्य उर्दू व्होकेशनल छात्रों सहित की परीक्षा होगी। गुरुवार 6 मई को विशिष्ट भाषा अंग्रेजी तथा द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी (व्होकेशनल

के छात्रों सहित)का प्रश्न पत्र होगा। शनिवार 8 मई को शारीरिक शिक्षा, नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के सभी विषय तथा व्होकेशनल कोर्स का प्रथम प्रश्नपत्र होगा। निर्धारित समय सारणी के अनुसार सोमवार 10 मई को भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन एण्ड हार्टीकल्चर, स्टिल लाइफ एण्ड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया-विज्ञान एवं स्वास्थ्य, बुककीपिंग एवं एकाउंटेंसी और तृतीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स की परीक्षा होगी। मंगलवार 11 मई को बायोटेक्नालॉजी तथा भारतीय संगीत एवं बुधवार 12 मई को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि मानविकी, होम साइंस, एन्वायरमेंटल एजुकेशन एवं रूरल डेवलपमेंट, इंटरप्रन्योरशिप, फाउंडेशन कोर्स तथा ड्राइंग एवं डिजाइनिंग के प्रश्नपत्र होंगे। बुधवार 13 मई को रसायन शास्त्र, इतिहास व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट ऑफ साइंस एण्ड मैथमेटिक्स, यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग और गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान की परीक्षा होगी। सोमवार 17 मई को मैथमेटिक्स तथा मंगलवार 18 मई को राजनीति शास्त्र का प्रश्नपत्र होगा। गुरुवार 20 मई को बायोलॉजी एवं शुक्रवार 21 मई को इन्फॉर्मेटिक प्रेक्टिसेस का प्रश्नपत्र होगा।

10वीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा

हाई स्कूल कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं 30 अप्रैल से आरंभ हो रही हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी आर.एन. पटेल ने बताया कि हाई स्कूल की परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होगी। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र शुरू होने से 15 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। प्रत्येक परीक्षार्थी का उपस्थिति पत्रक की फोटो से मिलान किया जायेगा। प्रवेश पत्र में भी फोटो लगाना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं के नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र शुक्रवार 30 अप्रैल विशिष्ट भाषा हिन्दी, द्वितीय व तृतीय भाषा सामान्य हिन्दी का प्रश्नपत्र होगा। शनिवार एक मई को नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय तथा सोमवार 3 मई को सामाजिक विज्ञान का प्रश्नपत्र होगा। मंगलवार 4 मई को विशिष्ट तथा सामान्य भाषा उर्दू एवं बुधवार 5 मई को दूसरी और तीसरी भाषा सामान्य संस्कृत का प्रश्नपत्र होगा। गुरुवार 6 मई को तृतीय भाषा मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी तथा केवल मूक बधिर छात्रों के लिये पेंटिंग एवं दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिये संगीत का पेपर होगा। शनिवार 8 मई को विज्ञान विषय तथा मंगलवार 11 मई को द्वितीय भाषा अंग्रेजी एवं सामान्य अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा। अंतिम प्रश्नपत्र 19 मई को गणित विषय का होगा।